“ग्राम” से किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता को मिलेगा एक मंच- भजनलाल शर्मा

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम 2026) के कर्टेन रेज़र कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया

जयपुर, 10 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसान मजबूत होगा तो देश-प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का सुदृढ़ इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कृतसंकल्प है। इसी क्रम में जयपुर में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम- 2026) का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेशभर के किसानों को खेती के नवीनतम आधुनिक तरीकों की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि “ग्राम” के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर रथ भेजे जाएंगे, जिससे किसान लाभान्वित हो सकें। इनमें सुझाव पेटिका भी रखी जाएगी, जिससे किसान योजनाओं से जुड़े अपने सुझाव भी दे सकें।

मुख्यमंत्री शर्मा ने शुक्रवार को राज्य ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक (ग्राम- 2026) मीट के कर्टेन रेज़र कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम-2026 एक ऐसा मंच होगा, जहां किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता मिलकर किसानों के सशक्तीकरण के लिए संवाद करेंगे। इस मीट के माध्यम से कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स पर एकेडेमिक-संस्थागत एवं विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ प्रदेश के किसानों को मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर में पश्चिमी क्षेत्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से कृषि उत्पादन, जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा और प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई थी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राज्य ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक (ग्राम- 2026) मीट के कर्टेन रेज़र कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

- **ग्राम 2026 का जयपुर में 23 से 25 मई को आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में शर्मा ने ग्राम 2026 के लोगो और ब्रोशर का अनावरण भी किया।**

इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसान पारम्परिक खेती से हटकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ें तथा खेती में नई-नई तकनीकों का उपयोग कर समृद्ध एवं खुशहाल बनें। ग्राम-2026 के माध्यम से किसानों को विश्वभर से आए कृषि विशेषज्ञों से नवीनतम तकनीकों की जानकारी मिलेगी। साथ ही, वे वैश्विक मंच से भी जुड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में हमारी सरकार किसानों को आगे बढ़ाने एवं उनके सम्मान के लिए निरन्तर कार्य कर रही है।

इस दौरान शर्मा ने ग्राम के लोगो का अनावरण एवं ब्रोशर का विमोचन किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, विभिन्न अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दक्षिणी राज्यों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्टालिन और अन्य मुख्यमंत्रियों ने इस असंतुलित परिसीमन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह बड़े राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, को ज्यादा ताकत देता है और अन्य राज्यों को असहाय छोड़ देता है।

साथ ही, छोटे राज्यों ने भी इसे स्वीकार करने से इनकार किया है, क्योंकि इससे उनकी भूमिका नगण्य हो जाएगी।

सितंबर 2023 में सरकार ने विपक्ष के समर्थन से एक बिल पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के आरक्षण को केवल जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है।

पर कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस महिलाओं के आरक्षण को लागू किया जाए और इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से प्रभावी किया जाए। अब सरकार एक अलग और जल्दबाजी वाली रणनीति अपना रही है, जो महिलाओं के आरक्षण के बजाय, राजनीतिक और रणनीतिक लाभ पर केन्द्रित है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष अब असमंजस की स्थिति में है, और वे संख्या प्रबंधन की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संविधान संशोधन बिल विपक्ष के समर्थन के बिना नहीं लाया जा सकता।

कच्चे रास्ते पर सो रहे परिवार को ट्रेलर ने कुचला

माँ-बेटी और भांजी की मौत, तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल

गुढ़ागौड़जी/झुंझुनूं, 10 अप्रेल (निसं)। थाना क्षेत्र जिले के नंगली दीपसिंह के समीप शुक्रवार अलसुबह ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। कच्चे रास्ते पर खुले आसमान के नीचे सो रहे एक भोपा परिवार पर अचानक मौत बनकर एक बेकाबू ट्रेलर चढ़ गया। भयावह हादसे में मां-बेटी और भांजी की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, भोपा समाज के रामस्वरूप और रूड़मल का परिवार गुरुवार शाम को ही नंगली दीपसिंह के पास एक खाली जगह पर आकर रुका था। रोजमर्रा की तरह सभी ने वहीं डेरा डाल लिया। रात को खाना खाने के बाद बच्चे और महिलाएं जमीन पर चादर बिछाकर खुले में सो गए। परिवार के साथ सो रहे लोगों में सुरेश भोपा की पत्नी होटकी, उसकी 13 साल की बेटी पायल उर्फ मोडी, 6 साल का बेटा संजय, 5 साल का बेटा संजीत, मुन्ना भोपा की 18 साल की बेटी रविना, 13 साल की बेटी प्रियंका, 8 साल का बेटा अनिल और 7 साल का बेटा सुनिल शामिल थे। सभी गहरी नींद में थे, तभी सुबह करीब चार बजे एक तेज रफ्तार ट्रेलर कच्चे रास्ते पर बेकाबू हो गया और सो रहे परिवार के ऊपर चढ़ गया, जिससे होटकी और उसके साथ सो रहे बच्चे बुरी तरह कुचल गए, जबकि अनिल बच गया। आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने तुरंत दौड़कर घायलों को संभाला। इस भयावह हादसे में होटकी की 13 वर्षीय बेटी पायल उर्फ मोडी की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को तुरंत गुढ़ागौड़जी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्रियंका को भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सभी घायलों को झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान होटकी ने भी दम तोड़ दिया। घायलों में चार बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इनमें तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रैफर किया गया है, जबकि रविना का इलाज झुंझुनूं के राजकीय बीडीके अस्पताल में चल रहा है। हादसे के तुरंत बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने ट्रेलर चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।

- **जिंदगी के लिए जूझ रहे बच्चों को जयपुर रैफर कर दिया गया है।**

बताया जा रहा है कि चालक ने अपने परिजनों को फोन कर बुलाया, जिनकी गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि चालक के परिजन घायलों को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद शुक्रवार सुबह जब परिजन पोस्टमार्टम के लिए गुढ़ागौड़जी पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने भोड़की चौराहे पर जाम लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी सीआई सुरेश रोलन ने समझाइश कर लोगों को शांत किया और जाम खुलवाया। सीआई ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है और आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पाक रक्षा मंत्री ने इज़रायल को “शैतान” और “मानवता के लिए अभिशाप” बताया

पर, इज़रायल के प्र.मंत्री नेतन्याहू की घुड़की के बाद यह पोस्ट डिलीट की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को अभूतपूर्व रूप से भड़काऊ काम किया, उन्होंने इज़रायल को “दुष्ट” और “मानवता के लिए अभिशाप” कहा, क्योंकि उसने यूएस-ईरान युद्धविराम के बीच लेबनान पर हमला किया। इस पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी नाराज़गी जताई।

आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट, जिसे अब डिलीट कर दिया है, में दावा किया कि “इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, लेकिन लेबनान में नरसंहार जारी है।”

उन्होंने लिखा, “इज़रायल निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहा है, पहले गाज़ा, फिर ईरान और अब लेबनान, रक्तपात बिना रुके जारी है।”

आसिफ ने आगे कहा, “मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने यूरोपीय यहूदियों को हटाने के लिए फिलिस्तीनी भूमि पर यह कैंसर जैसा राज्य बनाया, वे नर्क में जलें।”

- **ख्वाज़ा आसिफ ने इज़रायल की तुलना कैंसर से की और कहा, इज़रायल सिर्फ लड़ाई चाहता है। उनका इशारा समझौता वार्ता के बीच में इज़रायल द्वारा लेबनान पर हमला करने के संदर्भ में था।**
- **नेतन्याहू ने इस पर कड़ा विरोध जताया और कहा, इज़रायल को “कैंसर” बताने का अर्थ है, वे इज़रायल का खात्मा करना चाहते हैं और जो इज़रायल का विनाश चाहते हैं, हम उनसे लड़ेंगे।**

नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इज़रायल को नष्ट करने का आ ान “असहनीय” है।

नेतन्याहू के कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, “यह कोई ऐसा बयान नहीं है, जिसे कोई सरकार सहन कर सके, खासकर उस सरकार की तरफ से, जो शांति के लिए तटस्थ मध्यस्थ होने का दावा करती है।”

इज़रायल के विदेश मंत्री गिदेओन सार ने भी पाकिस्तान के नेतृत्व की सार्वजनिक रूप से निंदा की, यह दर्शाते हुए कि यह दो देशों के बीच एक दुर्लभ प्रत्यक्ष कूटनीतिक टकराव है, जो औपचारिक संबंध नहीं रखते।

सार ने इसे “साफ-साफ यहूदी-विरोधी भड़काऊ आरोप” बताया और चेतावनी दी कि इज़रायल को “कैंसर जैसा” बताना, वास्तव में उसके विनाश की मांग करना है। उन्होंने कहा कि इज़रायल “उन आतंकवादियों के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा, जो इसके विनाश की कसम खाते हैं”, और यह दर्शाया कि तेल अवीव इस्लामाबाद से निकल रहे कड़वे भाषण को गंभीरता से ले रहा है।

इस बीच, नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने लेबनान के साथ “जितनी जल्दी संभव हो, सीधे वार्ता” करने का आदेश दिया है। यह कदम तब आया है, जब यूएस, इज़रायल और ईरान के बीच दो सप्ताह के नाज़ुक युद्धविराम पर खतरा मंडरा रहा है, विशेषकर इज़रायल के लेबनान में सैन्य अभियान की तेज़ी के बाद।

उनके कार्यालय ने बयान में कहा, “लेबनान की बार-बार की मांग के मद्देनजर कि इज़रायल के साथ सीधे वार्ता खोली जाए, मैंने कल कैबिनेट को निर्देश दिया कि जितनी जल्दी संभव हो, लेबनान के साथ सीधी वार्ता शुरू की जाए।”

बयान में आगे कहा गया, “वार्ता का मुख्य उद्देश्य हिज़बुल्लाह को निरस्त्र करना और इज़रायल और लेबनान के बीच शांति संबंध स्थापित करना होगा। इज़रायल आज लेबनान के प्रधानमंत्री द्वारा बेरुत को निरस्त्रीकरण करने के आ ान की सराहना करता है।”

हुमायूँ कबीर के वीडियो के बाद ओवैसी ने तोड़ा गठबंधन

ओवैसी ने कहा, उनकी पार्टी ऐसी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती, जिससे मुसलमानों की ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह लग जाए

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। चुनाव से कुछ दिन पहले, तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की राजनीति में उस समय हलचल पैदा कर दी, जब उसने एक स्टिंग वीडियो जारी किया। वीडियो में आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) नेता हुमायूं कबीर वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ अपने संपर्क के बारे में बात करते दिख रहे हैं। वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है और कबीर ने इसे एआई जनित बताते हुए खारिज कर दिया है।

वीडियो में यह बातचीत है कि कबीर को मुसलमान मतदाताओं को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के लिए प्रभावित करने के लिए पैसा मिलेगा।

तृणमूल कांग्रेस ने किसी भी राजनीतिक नेता या पार्टी के खिलाफ कोई सीधे आरोप नहीं लगाए। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से, टीएमसी भाजपा को इसमें घसीट लायी और कहा कि यह कदम एक बड़ी राजनीतिक योजना का हिस्सा प्रतीत होता है। गैर-टीएमसी पार्टियों ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि यह वीडियो ऐसे समय पर जारी किया गया, जब चुनावों से पहले यह लोगों का अधिक ध्यान खींचेगा।

इस राजनीतिक नाटक के बाद, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की “आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी)” के साथ गठबंधन तोड़ दिया। दोनों नेता मुसलमान वोट बैंक को मजबूत करने के विचार से एक साथ काम मिलकर कर रहे थे, ताकि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया जा सके।

- **तृणमूल कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो जिसमें हुमायूँ कबीर को भाजपा नेताओं के साथ तृणमूल के खिलाफ साजिश रचते हुए दिखाया गया है, को हुमायूँ ने “एआई निर्मित” कहकर खारिज कर दिया।**
- **तृणमूल छोड़ने के बाद, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का आह्वान कर हुमायूँ कबीर ने मुसलमानों में पैठ बना ली थीं, पर, इस वीडियो से उनकी छवि बिगड़ी है और इससे तृणमूल को फायदा होने की उम्मीद है।**

एआईएमआईएम ने ऑनलाइन पोस्ट में कहा, “हुमायूं कबीर के खुलासे दिखाते हैं कि बंगाल के मुसलमान कितने संवेदनशील हैं। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान से जुड़ी नहीं रह सकती, जिसमें मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठता हो। आज एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन वापस ले लिया है।”

एआईएमआईएम ने आगे कहा कि वह बंगाल में स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ के लिए एकल स्तर पर काम करेगी। यह घोषणा उस दिन की गई, जब ओवैसी कबीर की पार्टी के साथ बीरभूम, आसनसोल और कोलकाता सहित जिलों में संयुक्त अभियान शुरू करने वाले थे।

इस घटनाक्रम से मुसलमान बहुल जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा और साउथ 24 परगना में टीएमसी की संभावनाएँ मजबूत हो सकती हैं।

कबीर, जो पूर्व में टीएमसी विधायक रह चुके हैं, ने मध्य बंगाल, खासकर मुर्शिदाबाद जिले में लोकप्रियता हासिल कर ली है, खासकर बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद बनाने के अपने आ ान के बाद। कबीर ने पिछले साल दिसम्बर में टीएमसी से निष्कासित होने के बाद अपनी पार्टी बनाई। कबीर अक्सर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते रहे हैं।

जस्टिस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस वर्मा ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी थी।

‘ट्रम्प ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की ओर धकेलते रहे हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन ने ऐसे प्रस्तावों को पहले ठुकरा दिया था। तुर्किए की सरकारी समाचार सेवा अनाडोलू एजेंसी (एए) ने बोस्टन पब्लिक रेडियो पर दिए एक इंटरव्यू के हवाले से बताया कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का रवैया बड़े वैश्विक और आर्थिक नतीजों को जन्म दे सकता है। उन्होंने मौजूदा नाजुक सीज़फायर पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने मौजूदा दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर पर सवाल उठाते हुए इसे बेहद ढीला-ढाला बताया। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी, जो एक पूर्व सीनेटर भी हैं और साल 2015 में उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौते में बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी।

प्र.मंत्री मोदी और ममता बनर्जी में तेज हुआ “फिश वॉर”

प्र.मंत्री मोदी ने कहा, ममता बनर्जी की गलत नीतियों के कारण बंगाली लोगों को अन्य राज्यों से मछली मंगानी पड़ती हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्वी मिदनापुर में एक सभा में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार मछली पालन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में विफल रही है, जबकि राज्य में इसकी भारी मांग है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से पूछा कि पिछले 15 वर्षों में यह क्या कर रही थी, क्योंकि मछली की अत्यधिक मांग वाले इस राज्य को इसकी कमी को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से मछली लानी पड़ रही है।

- **प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में मछली उत्पादन के भारी अवसर हैं, फिर भी राज्य आत्मनिर्भर नहीं है।**
- **ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को खुद को अपडेट रखना चाहिए, हम पहले आँध्र से मछली मंगाते थे, पर, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती।**

प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना का जवाब देते हुए, बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना में एक रैली में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बंगाल पहले आंध्र प्रदेश से मछली आयात करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को अपडेट रखें।

बनर्जी ने कहा, “मैंने सुना कि आज उन्होंने कहा कि बंगाल में मछली का उत्पादन नहीं होता, जबकि बिहार ज्यादा उत्पादन कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। लेकिन आप बिहार में लोगों को मछली खाने की अनुमति नहीं देते। यहाँ हम बाजार से मछली खरीदकर खाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में कहा, “पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग और सी फूड उत्पादन के मामले में बहुत बड़े अवसर हैं, यहाँ मछली की भारी मांग के बावजूद, राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है।”

उन्होंने इस जनसभा के एक वीडियो में कहा, “आज भी बंगाल को घरेलू मांग पूरी करने के लिए अन्य राज्यों से मछली आयात करनी पड़ती है। सत्ता में 15 साल रहने के बावजूद, तृणमूल कांग्रेस आपको मछली जैसी बुनियादी चीज़ भी उपलब्ध कराने में विफल रही, वह भी राज्य के बाहर से लानी पड़ती है।”

प्रधानमंत्री ने इस स्थिति के लिए ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला और कहा, “यह तृणमूल की भ्रामक नीतियों का एक स्पष्ट उदाहरण है। पिछले 11 वर्षों में भारत का कुल मछली उत्पादन दोगुना हो गया है।

भारत का सी फूड निर्यात दोगुना हो गया है। फिर भी, बंगाल में केवल तृणमूल सरकार की वजह से, जो उपलब्धि देश के बाकी हिस्सों में हासिल की गई, वह यहाँ नहीं हो पायी।”

रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भाजपा विधानसभा चुनाव जीतती है तो बंगाल के लिए छह गारंटियाँ दी जाएंगी। उन्होंने “क्रूर” तृणमूल सरकार को हटाने की मांग की तथा उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह “विकास की नई विफलताओं के मानक बना रही है और राज्य को पीछे धकेल रही है।”

सीज़फायर दो पार्टियों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाना चाहिए, कब तक टिकेगा।

तीसरा, संघर्ष का प्रॉक्सी के माध्यम से फैलाव, विशेषकर लेबनान और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में, जहाँ इज़रायल के अभियान व्यापक थिएटर को भड़काने का जोखिम उठाते हैं। इनमें से प्रत्येक आपस में जुड़ा हुआ है, और ये मिलकर ये संकट के अगले चरण को परिभाषित करते हैं।

होर्मुज़ स्ट्रेट अब भी सबसे महत्वपूर्ण लीवर बना हुआ है। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा इस संकरे मार्ग से गुजरता है, जिससे यह आर्थिक रक्तवाहिनी है, साथ ही धमनियों और रणनीतिक जाम के बिंदु, दोनों के रूप में काम करता है। ईरान के नियंत्रित व्यवधान ने सिर्फ कुछ देशों के जहाजों को पारगमन की अनुमति दी है और उसने स्ट्रेट बंद करने की क्षमता का संकेत भी दिया है। ईरान ने पहले ही दिखा दिया है कि असमानता पारंपरिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। पूरी तरह से बंद न होने पर भी, केवल अनिश्चितता ने शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम और ऊर्जा कीमतों को बढ़ा दिया है। भारत जैसे आयातक देशों के लिए, जोखिम केवल उच्च तेल बिल नहीं है, बल्कि वह अस्थिरता है, जो वित्तीय योजना और मुद्रास्फीति प्रबंधन को जटिल बनाती है।

सप्ताहों के बढ़ते तनाव के बाद प्रबंधित युद्धविराम अस्थायी शांति के अलावा कोई अधिक राहत नहीं देता। यह मुख्य विवादों को संबोधित नहीं करता: ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएँ, अमेरिका-इज़रायल सुरक्षा समीकरण, और विभिन्न संगठनों के माध्यम से तेहरान का क्षेत्रीय प्रभाव। वास्तव में, यह विराम सभी पक्षों को पुनर्गठित होने का अवसर देता है। वॉशिंगटन अपनी निवारक क्षमता की सीमाओं का मूल्यांकन कर सकता है; तेहरान दबाव के लचीलेपन का परीक्षण कर सकता है, बिना उस सीमा को पार किए, जो भारी प्रतिशोध को आमंत्रित करे। यह क्लासिक ब्रिंकमैनशिप है, जहाँ संयम सामरिक है, परिवर्तनकारी नहीं।

अधिक चिंताजनक बात यह है कि संघर्ष क्षेत्र में फैल रहा है। लेबनान में इज़राइल के लगातार हमले और ईरान समर्थित समूहों की लगातार गतिविधियाँ यह संकेत देती हैं कि युद्धक्षेत्र छोटा नहीं हुआ, बल्कि स्थानांतरित हुआ है। ऐसे प्रॉक्सी टकराव संभावित इनकार की अनुमति देते हैं जबकि दबाव भी बनाए रखते हैं। फिर भी, ये गलत आकलन का जोखिम बढ़ाते हैं। एक उच्च-हानि वाला हमला या गलत संकेत युद्धविराम को तोड़ सकता है और व्यापक संघर्ष को जन्म दे सकता है, जिसमें कई अभिनेता प्रतिस्पर्धी लाल रेखाओं के साथ शामिल हो सकते हैं।

आर्थिक परिणाम पहले ही दिखाई देने लगे हैं। तेल बाजारों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन द्वितीयक प्रभाव अधिक दीर्घकालिक साबित हो सकते हैं। शिपिंग मार्गों में व्यवधान न केवल ऊर्जा, बल्कि रसायन, उर्वरक और मैन्युफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण इनपुट को प्रभावित करता है। आपूर्ति श्रृंखलाएँ, जो पहले के झटकों से उबर ही रही हैं, फिर से तनाव का सामना कर रही हैं। वित्तीय बाजार, इस बीच, भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम को शामिल कर रहे हैं, जो अ्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नकद पूंजी की स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, इसका अर्थ मुद्रा दबाव और आयातित महंगाई होता है-एक असुविधाजनक मिश्रण, जब विकास अभी भी असमान है।

एक रणनीतिक सबक भी सामने आ रहा है। यह संघर्ष गहन राजनीतिक विवादों को हल करने में सैन्य श्रेष्ठता की सीमाओं को रेखांकित करता है। सटीक हमले और तकनीकी प्रभुत्व क्षमताओं को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य को समाप्त नहीं करते। भूगोल, प्रॉक्सी और आर्थिक जाम बिंदुओं का उपयोग करने की ईरान की क्षमता आधुनिक संघर्ष में व्यापक बदलाव को उजागर करती है, जहाँ प्रभाव नेटवर्क के माध्यम से लागू होता है, न कि मोर्चे से।

भारत के लिए, प्रभाव तत्कालिक है और इसकी कई परतें हैं। ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी सुरक्षा, और खाड़ी के माध्यम से व्यापार मार्ग, सभी परतें उजागर हो गई हैं। कूटनीतिक संतुलन, एक साथ अमेरिका, इज़रायल और ईरान के साथ संबंध बनाए रखना, में नयी कुशलता की आवश्यकता होगी। यह संकट भारत के ऊर्जा स्रोतों को विविधीकृत करने और रणनीतिक भंडार को मजबूत करने के प्रयासों को भी तेज कर सकता है।

अंत में, वर्तमान समय समाधान के बजाय पुनःसमायोजन के बारे में है। बंदूकें अस्थायी रूप से शांत हो सकती हैं, लेकिन मूल प्रतिस्पर्धा अब भी अनसुलझी है। आगे जो आने वाला है, वह स्थिरता की वापसी नहीं है, बल्कि अधिक जटिल संतुलन है, जहाँ तनाव प्रबंधित किया जाता है, मिटाया नहीं जाता, और अगली वृद्धि घोषित उद्देश्य से नहीं, बल्कि संचित घर्षण से उत्पन्न हो सकती है।

ईरान ने इस्लामाबाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दामाद जैरेड कुश्नर (जबरदस्ती) भी शामिल हैं।

ईरान ने पहले कह दिया था कि वह स्टीव विटकोफ या जैरेड कुश्नर के साथ बातचीत नहीं करेगा। दूसरी ओर, वैंस ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अमेरिका के साथ खेल नहीं खेला जाए और वार्ता ईमानदारी से हो।

इन सब जटिलताओं के बीच, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीबाफ ने कुछ बहुत कठिन शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा किए बिना वार्ता शुरू नहीं हो सकती।

गलीबाफ, जो संभवतया अब शक्तिशाली आईआरसीसी पर पूरी पकड़ रखने वाले असली सर्वोच्च नेता हो सकते हैं, ने मांग की कि वार्ता शुरू होने से पहले ईरान के सभी रोके गए फंड रिलीज़ किए जाएँ। अमेरिकी और पश्चिमी बैंकों में ईरानी फंड्स का एक बड़ा हिस्सा फ्रीज़ हैं, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के आधार पर रोके गए हैं। ये मुख्य रूप से ईरान की तेल से हुई आय हैं।

ईरानी फंड्स को रिलीज़ करना कभी भी युद्धविराम वार्ता का हिस्सा नहीं रहा। गलीबाफ ने इसे चतुराई से उस समय उठाया, जब ईरान के लिए यह सबसे सुविधाजनक था।

दूसरी शर्त के रूप में, ईरान यह जोर भी दे रहा है कि लेबनान का मुद्दा शामिल हो और लेबनान में युद्धविराम हो, तभी वार्ता शुरू हो सकती है। यह ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेबनान स्थित हिज़बुल्लाह ईरानी स्टेट की एक विस्तारित शाखा है।

हिज़बुल्लाह पर इज़रायल लगातार हमले कर रहा है और उसे नुकसान पहुँच रहा है। अगर यह लगातार जारी रहा, तो ईरान की अपनी संरक्षित शासन प्रणालियों का समर्थन करने की प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ सकती है। यह ईरान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके कई आभासी शासन विभिन्न रूपों में लड़ाई लड़ रहे हैं।

गलीबाफ अच्छी तरह जानते हैं कि ये शर्तें अमेरिका या इज़रायल तुरंत पूरी नहीं कर सकते। ये शर्तें ईरान को वार्ता के दौरान अन्य रियायतें निकालने का अवसर देती हैं। ये शर्तें वार्ता को मूल मुद्दे, होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने और उसमें स्वतंत्र पारगमन बहाल करने से भी भटका सकती हैं।

डॉनल्ड ट्रंप की पूर्व शर्तों में होर्मुज़ स्ट्रेट का तुरंत और बिना शर्त खुलना शामिल है। ट्रंप को एहसास है कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहा और ईरान के नियंत्रण में रहा, तो तेल की कीमतें स्थायी रूप से उच्च हो सकती हैं। पेट्रोल पंप पर तेल की कीमतें अमेरिकी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक हैं।

वार्ता की आंतरिक परिस्थितियों को देखते हुए, ट्रंप के लिए यह ईरानी नेताओं से अधिक जरूरी है कि एक उचित समझौता हो। ट्रंप के लोकप्रियता रेटिंग में जो सबसे अपमानजनक गिरावट आई है और यह मुद्दा उनके पुराने समर्थकों में भी निहित विरोध पैदा कर रहा है।

उच्च कीमतें अमेरिकी जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई हैं और वे इसका विरोध करने लगे हैं। रिपब्लिकनों और पूर्व एमएजीए समर्थकों में भी ट्रंप के युद्ध के आदेश के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है।

ईरान को लुभाने के लिए, ट्रंप ने अब ईरान के साथ टोल्स संग्रह के एक साझा उद्यम का प्रस्ताव रखा है। सामान्यतः, किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी तटीय देश को पारगमन के लिए टोल लेने का अधिकार नहीं है। फिर भी, ट्रंप अब ईरान के साथ साझा टोल लेने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

नीतीश ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सम्राट चौधरी सहित अन्य उपस्थित थे।

69 वर्षीय हरिवंश का पिछला कार्यकाल 09 अप्रैल को पूरा होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उनको मनोनीत किया। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा होने के बाद एक सीट रिक्त हो गयी थी। राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इन सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चुना जाता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908